बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 147 ● नई दिल्ली ● बुधवार 25 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी केस में सोनू पंजाबन को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपीलें मंजूर की

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराई गई गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और संदीप बेडवाल की अपीलों को मंजूर कर लिया है। दोनों ने वर्ष 2020 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में ट्रायल कोर्ट ने गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और उस पर 64,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

पीएम मोदी की इस्राइल यात्रा गलत फैसला था, पश्चिम एशिया में पाक की मध्यस्थता की खबरों पर बिफरी कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि अगर पाकिस्तान द्वारा अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की खबरें सही हैं, तो यह भारत के लिए बड़ा झटका और नाकामी की बात है। विपक्षी पार्टी ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य सफलता के बावजूद, पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता और नैरेटिव प्रबंधन मोदी सरकार से काफी बेहतर रहा है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की कई रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच एक मध्यस्थ बताया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर ये रिपोर्ट्स सही हैं, तो यह भारत के लिए बड़ा झटका है और खुद को विश्वगुरु बताने वालों को करारा जवाब है। रमेश ने कहा कि पिछले एक साल में यह साफ हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता और वैश्विक स्तर पर अपनी बात रखने की रणनीति भारत से बेहतर रही है। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से मजबूत होता दिख रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस व्यक्ति

के साथ नजदीकी दिखाई, जिसकी भड़काऊ बयानबाजी पहलगाम आतंकी हमले का आधार बनी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को दो बार व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की हालिया इस्राइल यात्रा को गलत फैसला बताते हुए कहा कि यह यात्रा उस समय समाप्त हुई, जब अमेरिका-इस्राइल द्वारा ईरान पर हवाई हमले शुरू होने वाले थे, जिससे भारत की संभावित मध्यस्थ की भूमिका कमजोर हुई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका एक सम्मानित ईरानी नेता के संपर्क में है और ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते को लेकर इच्छुक है। हालांकि, उन्होंने उस नेता का नाम बताने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका मोजतबा खामेनेई से बातचीत नहीं कर रहा है। वहीं, ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार किया है, लेकिन यह माना है कि क्षेत्र के कुछ देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तुर्किये, मिस्र और पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान-प्रदान करा रहे हैं। बताया गया कि इन देशों के विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से अलग-अलग बातचीत की। 28 फरवरी से अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में फैल गया।

महिला आरक्षण कानून- संसद में आ सकते हैं दो नए विधेयक, विपक्ष बोला- सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार

नई दिल्ली । केंद्र सरकार संसद के मौजूदा बजट सत्र में महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लागू करने के लिए दो नए विधेयक लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना है कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस बीच, कई विपक्षी दलों ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। विपक्ष का कहना है कि यह बैठक मौजूदा विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद आयोजित की जाए।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के सदन के

नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की। ताकि आम सहमति बन सके। यदि सहमति बनती है, तो ये दो विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किए जा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मामले को लेकर कई दलों की महिला सांसदों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। जदयू सांसद लवली आनंद ने इसे एक सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी से देश की प्रगति तेज होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधी आबादी से किए गए वादे को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के प्रयास महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रहे हैं, जिससे नीति-निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ेगी। वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने पहल का स्वागत करते हुए कार्यान्वयन की स्पष्टता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरक्षण के मानदंड और व्यवस्थाएं क्या होंगी। हम सरकार की इस पहल से खुश हैं। संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी स्वीकृति दी थी। यह प्रावधान परिसीमन अभ्यास के बाद लागू होना है, लेकिन सरकार इसे जल्द प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है।

हाई अलर्ट पर भारत- बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच रक्षा तैयारियों की समीक्षा, राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक कर देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। वहीं पिछले दिनों 22 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस बैठक हुई थी, जिसमें ऊर्जा और उर्वरक सप्लाई की समीक्षा की गई थी। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और डीआरडीओ के चेयरमैन समीर कामत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशनल तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब चौथे सप्ताह में पहुंच चुका है। इससे होर्मुज स्ट्रेट के जरिए होने वाले व्यापार पर असर पड़ा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर दबाव बढ़ा है।

एम्स में हरीश राणा का निधन:13 साल तक कोमा में रहने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से मिली थी इच्छा मृत्यु की इजाजत

नई दिल्ली। भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का निधन हो गया है। हालांकि, एम्स ने समाचार लिखे जाने तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। अंतत भारत में पहली बार परोक्ष इच्छामृत्यु के तहत एक इंसान को उसके 13 वर्ष पुराने दर्द से मुक्ति मिल गई। गाजियाबाद के हरीश राणा ने एम्स के विशेषज्ञों की देखरेख में अंतिम सांस ली। एक दुर्घटना का शिकार होने के बाद कोमा में जाने के बाद हरीश का इलाज करने के लिए उनके माता-पिता और भाई ने अथक प्रयास किया। देशभर में विशेषज्ञों की राय ली। जिसने जो बताया, वैसा इलाज कराया मगर कोई सफलता हाथ न आई। अंत में अपने बच्चे को गौरवपूर्ण मृत्यु दिलाने के लिए वे सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर पहुंचे। कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। परिवार के सदस्यों ने हरीश राणा की मौत के बाद उनके क्रियाशील अंगों को दान करने की इच्छा जताई थी। हालांकि, हरीश राणा के मामले में परिवार द्वारा अंगदान का संकल्प जताए जाने के बाद अब यह एम्स की मेडिकल टीम की जांच पर निर्भर करेगा कि उनके शरीर के कौन-कौन से अंग प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त हैं और कौन से नहीं। एम्स के सूत्रों के अनुसार कार्यशील पाए जाने पर हरीश राणा की किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय और आंत जैसे अंगों के दान पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा कार्निया और हृदय के वॉल्व को भी दान देने पर बात की जा सकती है। मूलत-हिमाचल प्रदेश के रहने वाले परिवार के बेटे हरीश राणा की परोक्ष इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को एम्स के डॉक्टरों की देखरेख में चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया

केवल हिंदू-बौद्ध-सिख ही...धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा पाने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा करने के योग्य नहीं हो सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और एनवी अंजारिया की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म अपनाने और सक्रिय रूप से उसका पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। यह फैसला पादरी चिंथदा आनंद द्वारा दायर अपील पर आया, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा जाति आधारित भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करता है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता। किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। अपने गांव में रविवार की प्रार्थना कराने वाले पादरी आनंद ने आरोप लगाया कि अक्काला रामिरेड्डी और अन्य लोगों ने बार-बार उन पर हमला किया, उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और जातिगत आधार पर उनका अपमान किया। आनंद ने उनके खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। आरोपियों ने तर्क दिया कि आनंद ने ईसाई धर्म अपना लिया था और वे सक्रिय रूप से पादरी के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए वे अनुसूचित जातियों को मिलने वाले विशेष संरक्षण के हकदार नहीं थे। जांच पूरी होने और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, आनंद ने आरोपों को रद्द करने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया। लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने ईसाई धर्म अपनाने के बाद अपनी अनुसूचित जाति की स्थिति खो दी थी और इसलिए वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होने से भी उनके मामले में कोई सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां जातिगत भेदभाव को मान्यता नहीं दी जाती है, वहां धर्मांतरण अनुसूचित जाति की स्थिति को अमान्य कर देता है। इसके बाद आनंद ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। बेंच ने कहा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का यह दावा नहीं है कि उसने ईसाई धर्म से अपने मूल धर्म में पुनः धर्मांतरण किया है या उसे मदीका समुदाय में पुनः स्वीकार कर लिया गया है।

संत कबीर बस्ती संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक राजेश जून से कॉलोनी को पक्का कराने के लिए दिया माँग पत्र

बहादुरगढ़ - बहादुरगढ़ संत कबीर बस्ती संघर्ष समिति के पदाधिकारियो के द्वारा स्थानीय विधायक से कॉलोनी को पक्का कराने के लिए एक मांगपत्र सौपा। बतादे की आज संत कबीर बस्ती को पक्का कराने के लिए एक मांगपत्र संत कबीर बस्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार की अध्यक्षता मे समिति के पदाधिकारीयों स्थानीय विधायक राजेश जून को उनके कार्यालय पर दिया गया। अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया की करीब पिछले साठ सालो से हमारी कॉलोनी यहां साथपित है। और सरकार द्वारा लगाए गए बिजली के मीटर भी लगे हुए है। चुल्ह टेवस की पर्ची भी समय समय पर

कटवाई जाती है। साथ ही पूर्व नेताओं की शिलापट भी लगी हुई है। जिससे यह परमाणित होता है की हमारी कॉलोनी पिछले साठ सालो से यहां बसी हुई है। अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया की पिछले दिनों रविदास जयंती पर मंत्री कृष्ण लाल पंवार द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष यह माँग रखी थी जिसमे बीस साल से एक जगह पर रह रहे सष्ट, स्क, ओबीसी गरीब समाज के लोगो की कॉलोनी को पक्का कर उनको मालिकाना हक़ दिया जाए। जिसपर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी ने आस्वासन दिया था की ऐसा प्रपोजल लाया जाएगा जिसमे एक पैमाना तैयार किया जाएगा और इस तरह की कॉलोनीयो को रिजनेबल सा शुल्क लगाकर पक्का किया जाएगा। और सष्ट, स्क, ओबीसी के लोगो को मालिकाना हक़ दिया जाएगा। वही इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजेश जून ने समिति को आस्वासन दिया की पुरजोर तरिके से आपकी आवाज को उठाया जाएगा । वही महासचिव विजय ने बताया की हमारी समिति के प्रयासों से चौपाल की कार्यवाही भी चली हुई है और चौगान माता के साथ मे पड़ी खाली जमीन मे को साफ किया जा रहा है और यहां पर साफ सफाई कर मलवा डाला जा रहा है। इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता मे समिति के उपाध्यक्ष मोहित, महासचिव विजय, सचिव अजय कुमार, समिति सलाहकार सतीश सारसर,मिडिया प्रभारी राजपाल प्रधान, समिति सदस्य कर्मवीर, समिति के सह सचिव संजय किराड़, सेठा, ताराचंद फौजी व अन्य लोग मौजूद रहे

दुबई पर क्यों हमले कर रहा है ईरान?

मौजूदा जंग में ईरान का इरादा बिल्कुल साफ है कि अमेरिका और इजराइल के आगे झुकना नहीं है। मध्य-पूर्व के जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन पर हमला करते रहना है। मगर दुबई में तो कोई अमेरिकी सैन्य अड्डा है ही नहीं, फिर ईरान क्यों शांतिप्रिय दुबई पर हमले कर रहा है? यह सवाल इन दिनों हर किसी के मन में है, क्योंकि यह केवल एक शहर नहीं बल्कि आधुनिक कुबेर नगरी है। यहां के कण-कण में धन है। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो यहां दुनिया के करीब 200 देशों के लोग रहते हैं। पिछले साल करीब दो करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने दुबई की यात्रा की। हर किसी की तमन्ना होती है कि वह दुबई जरूर जाए। दुबई जाने की तमन्ना से मुझे एक पाकिस्तानी फिल्म याद आ गई जिसका नाम थाऱ्चलो दुबई! पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर रियाज बटालवी ने 1979 में यह फिल्म बनाई थी, जब ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए दुबई को केवल आठ साल हुए थे। कई बार सोचता हूं कि क्या बटालवी को यह अंदाजा था कि दुबई की किस्मत बुलंदी के शिखर को छुएगी? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि आज दुबई में लाखों-लाख भारतीय और पाकिस्तानी रहते हैं। वैसे अभी तो दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा करीब-करीब बंद कर रखा है। सवाल यह है कि करीब आधी सदी पहले जिस दुबई की पहचान आपस में लड़ने वाले कबीलों, मछली पकड़ने, सागर से मोतियों को निकालने और छुटपुट व्यापार करने वाले कोस्टल एरिया के रूप होती थी, उसने पिछले पचास वर्षों में ऐसी बेमिसाल तरक्की कैसे कर ली? आप सोच रहे होंगे कि ईरान के हमलों की बात करते-करते मैं दुबई के विकास की बुलंदियों की बात क्यों करने लगा? दरअसल हमलों के पीछे यही बुलंदी है इसलिए पहले दुबई की बुलंदी को समझना जरूरी है। जब भी हम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की बात करते है तो सबसे पहले दुबई का ख्याल जेहन में आता है लेकिन वास्तव में यूएई सात अमीरातों (रियासतों) का समूह है। इसमें दुबई के अलावा अबुधाबी, शारजाह, उम्मुल क्वैन, अजमान, अल फुजैरा और रास-अल-खैमा शामिल हैं। यूएई की राजधानी अबुधाबी है। इन सभी को 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से आजादी मिली। अगले ही दिन रास-अल-खैमा को छोड़कर बाकी सभी ने एक संघ बना लिया। करीब दो महीने बाद ईरान ने होर्मुज जलमार्ग के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो रास-अल-खैमा भी यूएई में आ मिला ताकि ईरान से जंग की स्थिति में वह कमजोर न पड़े। इस तरह से ईरान के साथ का विवाद यूएई से आ जुड़ा। तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव बने हैं। आज दुबई जिस बुलंद मुकाम पर है उसमें निश्चय ही वहां के शासक शेख मोहम्मद की दूर दृष्टि है। दुबई के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में तेल की हिस्सेदारी केवल एक प्रतिशत है, मगर उन्होंने परिस्थितियां ऐसी तैयार कर लीं कि देश वैभव की राह पर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। नजरिया बहुत स्पष्ट है। आओ, यहां काम करो, व्यापार करो, खाओ-पियो, मौज करो लेकिन नो नॉनसेंस! वहां पूरी तरह कानून का राज है। देश टैक्स फ्री है। व्यापार के लिए ईज ऑफ डूइंग के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि दुबई इस समय दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है। मुहावरे की भाषा में कहें तो जहाज भर-भर कर सोना आता है।

दुनिया भर का धन यहां पार्क होता है। यहां तक कि दूसरे देशों के माध्यम से इजराइल और चीन का भी यहां निवेश है। कभी डायमंड बिजनेस बेल्जियम और इजराइल में फलफूल रहा था लेकिन अब दुबई इसका हब है। यूएई और खासकर दुबई में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, यहां तक कि क्रिकेट को भी उन्होंने अपने यहां स्थापित कर लिया। दुबई अचंभित कर देने वाले निर्माण और शानो-शौकत की बेमिसाल इबारत लिखता जा रहा है, जैसा कि कभी यूरोप करता था। दुबई में बुर्ज खलीफा, पाम जुमेराह, दुबई मरीना, जुमेरा लेक टावर्स, जुमेराह हाइट्स जैसे आधुनिक निर्माण आश्चर्य से भर देते हैं। पाम जुमेराह मानव निर्मित द्वीप है और कमाल की बात है कि इसके निर्माण के लिए कांक्रीट या लोहे का उपयोग नहीं किया गया। समुद्र से 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाल कर पाम जुमेराह द्वीप बनाया गया। दुबई मेट्रो अपने आप में एक अद्वितीय प्रोजैक्ट है। दरअसल दुबई ने जो सोचा, उसे आकार दे दिया। दुनियाभर से बेहतरीन काम करने वालों को आकर्षित करने के लिए दुबई वह सब कर रहा है और करता रहा है जो जरूरी है। विदेशियों के लिए यहां तक छूट है कि अविवाहित जोड़े एक साथ रह सकते हैं और बच्चा हो जाए तो वह भी स्वीकार्य है। यानी दूरगामी सोच यूएई की खासियत है। उसने हर देश के साथ दोस्ताना रिश्ता रखा है। एक तरफ आलीशान मस्जिदें बनाई हैं तो दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता की भावना का आदर करते हुए अबुधाबी में हिंदू मंदिर की इजाजत दी। अब असली सवाल कि यूएई और खासकर दुबई पर ईरान हमले क्यों कर रहा है? अब तक 2000 से यादा मिसाइलें और ड्रोन ईरान दाग चुका है। यादातर को नाकाम कर दिया गया लेकिन बहुत सी मिसाइलें और ड्रोन दुबई पर गिरे भी है। दुबई एयरपोर्ट पर भी धमाके हुए हैं। लोगों की जानें भी गई हैं। मकसद साफ है कि दुबई के सुरक्षित होने के विश्वास को खंडित किया जाए ताकि दुनिया भर में दुबई को लेकर ऐसा भय व्याप्त हो जाए कि लोग इधर का रुख करें ही नहीं! क्या ईरान को इसमें सफलता मिलेगी? परिणाम जो भी हो, लेकिन ईरान का इरादा बुलंद है कि तुम अमेरिका के साथ हो तो तुमको छोड़ेंगे नहीं लेकिन कल्पना कीजिए कि जिन लोगों पर मिसाइलों की बरसात हो रही है उनकी जिंदगी कितनी सांसत में होगी। मगर आम आदमी के बारे में सोचता कौन है। सांडों की लड़ाई में खेत रौंदा ही जाता है। आज यूनाइटेड नेशन और शांति का राग अलापने वाली सारी संस्थाएं बेमानी हो गई हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। अमेरिका दुनिया का लीडर खुद को कहता है तो उसे लीडर की तरह व्यवहार भी करना चाहिए।

सम्पादकीय...

महादेवी प्रयाग की गंगा

कवि शिरोमणि निराला ने कभी महादेवी वर्मा कवयित्री के व्यक्तित्व को उक्त पंक्तियों से समझने की कोशिश की थी। एक जापानी कवि नागूची ने कहा था कि- महादेवी प्रयाग की गंगा है। आधुनिक हिन्दी साहित्य की जिन छह महान विभूतियों ने निर्विवाद रूप में अमरता प्राप्त कर ली है, उनमें महादेवी का स्थान विशिष्ट है। अन्य पांच विभूतियां हैं- भारतेंदु, मैथिलीशरण, जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। महादेवी में छायावादी कविता को एक गति वेग दिया, उसकी श्रृंगार-भावना को सौम्य और सौंदर्य चेतना को सूक्ष्म बनाया, कविता को अपनी सहृसानुभुति संपन्न चित्रकला से एक अपूर्व रंजकता प्रदान की और हमें संस्कृत की समृ संस्कृति से अनुप्राणित कर एक समर्थ गद्य शैली दी। एक छायावादी कवयित्री के रूप में भी महादेवी वर्मा की अपनी मौलिकता है। उन्होंने दीपक, बादल, वीणा इत्यादि के बिंबों में सुनिश्चित अर्थ बता भरकर छायावादी कविता को एक प्रतीक पद्धति दी। तथा छायावादी वेदना-संसार को रहस्यवादी संकेतों से उदात्त बनाया। लेखनी के साथ तूलिका पर भी अधिकार रखने के कारण उन्होंने चित्रोपन बिंबों की एक अभिनव योजना से छायावादी काव्य संसार को रंगरूप मय बना दिया। कितना विशाल, कितना मूर्त, कितना क्रियाशील और कितना रंग-बोधमय है यह बिंब। अवनि अंबर की रुपहली सीप में तरल मोती सा जलधि जब कांपता तैरते घन मृदुल हिम के पुंज से योत्सना के रजत पारावार में कवयित्री और चित्रकर्ती के दुर्लभ संयोग ने महादेवी वर्मा को आधुनिक हिन्दी साहित्य, भारतीय साहित्य तथा विश्व साहित्य के इतिहास में बहुत ऊंचे स्थान का अधिकारी बना दिया है। महादेवी ने चित्रकला की कोई विधिवत् शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। बचपन में एक मराठी सज्जन ने उन्हें चित्रकला की प्रारंभिक बातें सीखी दी। महादेवी वर्मा का जन्म सन् 1907 में 26 मार्च को होली के दिन फरूखाबाद में हुआ था। शायद होली का ही असर था कि उनकी तूलिका हमेशा रंग बिरंगी रही। उनकी कविताओं में विषाद और आंसू की जैसी भी घनघटा है। बातचीत के दौरान स्वजनों के साथ बहुत खुलकर हंसा करती थीं। और कभी-कभी अपने विनोदी स्वभाव का परिचय देने से न ही चूकती थीं। महादेवी वर्मा के पिताश्री गोविंद प्रसाद वर्मा कालिजियेट स्कूल, भागलपुर में कई वर्षों तक हेडमास्टर रहे। महादेवी इसीलिये अक्सर भागलपुर आती रहती थीं। लगातार कई दिनों तक रुका करती थीं और कभी कभार उस स्कूल के छात्रों को पढ़ा भी दिया करती थीं। इसलिये कवयित्री के मन में और उनके भाव-जगत में बिहार प्रवास का संस्कार रचा-बसा हुआ था। उनके लिये बिहार घर-नैहर जैसा था। महादेवी केवल कवयित्री, चित्रकत्री और उत्कृष्ट गद्यलेखिका ही नहीं थीं। वे एक दार्शनिक भी थीं, संस्कृत भाषा-साहित्य की परम विदुषी थीं। वक्तृत्व कला में निपुण थीं, श्रृंखला की कड़ियों को तोड़ने वाली एक विद्रोहिणी नारी थीं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली अग्रणी महिला थीं, शिक्षा शास्त्री थीं. उन में संगठन करने का अद्भुत कौशल था। और एक छायावादी कवयित्री होकर भी वे अपने समय समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवीय दायित्वों के प्रति अत्यधिक सजग थीं। चांदनी के देश जाने का, अभी ता मन नहीं है अश्रु- यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है।। किन्तु काल को कौन रोक सकता है कवयित्री की जिजीविषा भी काल को नहीं रोक सकी और बलशाली काल 11 सितंबर 1987 की काली रात में लगभग साढ़े नौ बजे अपना कवल निर्मम ग्रास से भर गया।

कांग्रेस को अहमद पटेल की कमी खली

हिंदी पट्टी के एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के इस दिग्गज नेता के ताजातरीन बयानों पर गौर फर्माइए जिसमें वे डंके की चोट पर कुबुलनामा करते हैं कि 'न तो हमारा नेता मजबूत है और न ही अब हमारे पास अहमद पटेल जैसे कोई काबिल पॉलिटिकल मैनेजर ही बचे हैं, भगवान जाने पार्टी आगे सरवाईव कैसे करेगी' सच पूछिए तो आज कांग्रेस की यह चिंता सार्वभौम हो गई है, हालिया रायसभा चुनावों में जो हरियाणा, बिहार ओडिशा में हुआ, असम में पार्टी के बड़े नेताओं ने जिस तरह भाजपा का रुख किया है इससे निश्चय ही कांग्रेस शीर्ष की पेशानियों पर बल पड़े होंगे। आइए सबसे पहले असम चलते हैं जहां 51 सालों तक लगातार कांग्रेसी रहे नौगांव के दो बार के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने आखिरकार कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा का दामन थाम लिया, इससे पहले वहां फरवरी में ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा भी कांग्रेस छोड़ भाजपा के पाले में चले गए थे। बोरदोलोई के बारे में माना जाता है कि वे पिछले कोई दो वर्षों से पार्टी में उपेक्षित चल रहे थे क्योंकि उन्होंने अध्यक्षीय चुनाव में हाईकमान की पसंद रहे मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह शशि थरूर का समर्थन कर दिया था। शायद इसी वज़ह से वे दिल्ली की आंखों में चुभने लगे थे। सो, जब इस बार असम में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुईं तो राहुल गांधी ने असम की बागडोर अपने अति प्रिय गौरव गोगोई के हाथों में सौंप दी। सूत्रों की मानें तो गौरव कांग्रेसी उम्मीदवारों की जो लिस्ट फाइनल कर रहे थे उसमें बोरदोलोई के लोगों के लिए जगह ही नहीं बन पा रही थी, मामले ने यहीं से तूल पकड़ा और प्रद्युत का विद्रोह धीरे-धीरे आकार लेने लगा। हालांकि असम में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की सिरमौर प्रियंका गांधी ने भी स्वीकार किया कि 'वे यानी कि बोरदोलोई टिकटों के बंटवारे को लेकर असंतुष्ट थे।' हालांकि बोरदोलोई के लिए कांग्रेस छोड़ने का फैसला इतना आसान कतई नहीं था, क्योंकि वे 1975 से लगातार कांग्रेस में ही बने हुए थे। सूत्रों की मानें तो भाजपा में जाने के फैसले पर पहुंचने से पूर्व उन्होंने कोई दो बार राहुल गांधी को फोन किया, पर राहुल ने जब उनका फोन ही नहीं लिया तो उन्होंने एक चुभता हुआ संदेश राहुल को लिखा, जिसका मजमून था कि 'इससे पहले कि मैं अपने किसी आखिरी निर्णय पर पहुंचूं, प्लीज कॉल मी बैक।' तब भी राहुल का फोन नहीं आया, हां उनका एक मैसेज जरूर आया- 'टॉक टू गौरव गोगोई।' बोरदोलोई ने समझ लिया कि दिल्ली के मन में उनके लिए क्या चल रहा है, सो कोई पांच दशक बाद उन्होंने भी अलग राह पकड़ ली। हरियाणा में भी हार करीब थी- इस दफे का हरियाणा रायसभा चुनाव भी कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया था। सूत्रों की मानें तो हरियाणा सरकार के पूर्व अधिकारी कर्मवीर बौद्ध को उम्मीदवार बनाने का फैसला राहुल गांधी का अपना निजी फैसला था, इस दलित अधिकारी के नाम का सुझाव राहुल को उनके सलाहकार के.राजू ने दिया था। सो, राहुल ने इस बारे में हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं से कोई सलाह-मशविरा किए बगैर बौद्ध की उम्मीदवारी पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी। वैसे गिनती के नजरिए से देखें तो बौद्ध की जीत में कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन्हें जीत के लिए महज़ 31 विधायकों के वोट चाहिए थे, जबकि हरियाणा में कांग्रेस के 37 निर्वाचित विधायक हैं लेकिन जब रिजल्ट आए तो ये बेहद चौंकाने वाले थे, बौद्ध को सिर्फ 28 वोट मिले। 9 कांग्रेसी विधायकों के वोट बर्बाद हो गए। 4 के वोट अवैध करार दिए गए जबकि 5 ने क्रॉस वोटिंग कर दी। यह तो शुक्र मनाइए कि भाजपा के भी एक विधायक का वोट अवैध करार दिया गया, वरना बौद्ध को जीत के लाले पड़ जाते। सबसे हैरत की बात तो यह है कि बौद्ध के पक्ष में वोट दिलवाने के लिए भी कांग्रेस नेतृत्व को काफी कवायद करनी पड़ी, पहले तो उन्हें अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश के एक अज्ञात स्थल में छुपा कर रखना पड़ा पर इसके बावजूद भी खेला हो गया। सबसे हैरत की बात यह कि हुड्डा की बेहद करीबी माने जाने वाली कांग्रेसी विधायक गीता भुक्कल पर भी क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लग रहे हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में दो मुस्लिम हैं और 2 विधायक सिरसा से हैं, जहां से कुमारी सैलजा सांसद हैं। अब कांग्रेस हाईकमान क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्यवाही करने का मन बना रहा है। ओडिशा में भी कांग्रेस का दांव उल्टा - ओडिशा के रायसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन से सांसद बने उद्योगपति व निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे समर्थन के लिए पहले कांग्रेस के पास गए थे। उन्होंने अपने समर्थन के लिए नवीन पटनायक को भी मना लिया था। इस चुनाव से पहले दिलीप रे दिल्ली भी गए थे, कहते हैं यहां उनकी अहम मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी हुई थी। समझा जाता है कि कांग्रेस के इन दोनों शीर्ष नेताओं के समक्ष रे ने दावा किया था कि 'अगर कांग्रेस उन्हें समर्थन दे देती है तो वे इसके बाद भाजपा के भी 4-5 विधायक तोड़ने में सक्षम हैं।' कहते हैं रे दिल्ली की इस मुलाकात से संतुष्ट थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस उनके साथ आएगी, पर किसी कारणवश ऐन वक्त कांग्रेस पलट गई और रे को आखिरी वक्त भाजपा की शरण में जाना पड़ा। पर उन्होंने जाते-जाते कांग्रेस के किले में एक बड़ी सेंध लगा दी, जहां 3 कांग्रेसी विधायकों ने उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। रे ने अपने इस कदम से एक तरह से कांग्रेस शीर्ष को ही आइना दिखाने का काम किया। ममता के निशाने पर ज्ञानेश - पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद के साथ ही यहां की सियासत रोज एक नई करवट ले रही है। ताजा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर काफी पहले से ज्ञानेश कुमार को अपने निशाने पर लिया हुआ है। अब संयुक्त विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया है। ममता ने 'एसआईआर' यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग चलाने की मांग की है। ममता ने संयुक्त व एकजुट विपक्ष का आह्वान करते हुए कुल 193 सांसदों के समर्थन का दावा किया है, जिसमें लोकसभा के 130 और रायसभा के 63 सांसद शामिल हैं। यह पहली मर्तबा है कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाने की बात हो रही है। भारत के संविधान के अनुछेद 324 (5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही महाभियोग के समान प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। पर लगता नहीं कि यह सब इतनी जल्दी-जल्दी हो पाएगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को ही आहूत है, सो यह महाभियोग प्रस्ताव इतनी जल्दी पारित हो पाएगा, इसमें संदेह ही है। महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले एक जांच समिति गठित की जाती है, और इस जांच समिति के रिपोर्ट आने की भी कोई समय-सीमा भी तय नहीं है। यानी यह प्रक्रिया निहायत ही लंबी है, तब तक बंगाल के चुनाव भी पूरे हो जाएंगे। पर ममता इस महाभियोग के बहाने अपने मतदाताओं से यह साफ-साफ कहना चाह रही हैं कि 'भाजपा इस चुनाव में जब पिछड़ रही है तो वह एसआईआर में गड़बड़ियां कर चुनाव जीतना चाहती है और इसको अंजाम देने वाले ज्ञानेश कुमार ही हैं।' इस चुनाव में टीएमसी का सीधा मुकाबला भाजपा से ही है। भाजपा का अपने बूथ प्रबंधन, जमीनी स्तर पर फैले संघ के नेटवर्क, वोटों के धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण और ममता के एंटी इंकंबेंसी मुद्दे को भुनाने पर जोर है तो वहीं ममता ने इस चुनाव को बंगाल के अस्मिता का मुद्दा बना दिया है। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के अलावा ममता का फोकस ग्रामीण व महिला वोटरों पर है। राय सरकार की कई नई योजनाएं इन्हीं वोटरों को मद्देनज़र रखते शुरू की गई है, इसके अलावा ममता की पार्टी का जमीनी स्तर पर फैले उसके संगठन की एक ताकत भी है जो इस चुनाव में उसका बेड़ा पार लगा सकती है। क्या रंग लाएगी केसी की कोशिश- पुराने सियासी रंग में पगे धुरंधर समाजवादी नेता केसी त्यागी अब जदयू छोड़ अपने लिए नए सियासी आशियाने की तलाश में हैं। वे लंबे समय तक दिल्ली में नीतीश व जदयू के 'प्वाइंट मैन' की तरह आचरण करते रहे हैं। दिल्ली के शीर्ष सियासी नेताओं और मीडिया के एक बड़े वर्ग में उनका अच्छा रसूख है। सो, अपना पुराना घर जदयू छोड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने का वक्त मांगा। उन्हें आसानी से अखिलेश से मिलने का वक्त मिल भी गया। दोनों नेताओं के बीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में एक अच्छी बातचीत हुई। अखिलेश चाहते थे कि 'केसी त्यागी सपा वॉइन करें और पश्चिमी यूपी में सपा का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करें, क्योंकि केसी त्यागी की न सिर्फ त्यागी समाज के वोटरों में एक अच्छी पैठ है, बल्कि गुर्जर बिरादरी से भी उनके निजी ताल्लुकात बहुत बढ़िया हैं।' इस अर्थपूर्ण मुलाकात के बाद केसी त्यागी का रालोद के जयंत चौधरी से मिलने जाना एक नई सियासी उलझनें पैदा कर रहा है, आखिर जयंत के पास ऐसा क्या है जो केसी को ऑफर कर सकते हैं अपने विधायकों के दम पर तो वे उन्हें रायसभा भी नहीं भेज सकते, जबकि अखिलेश चुटकियों में यह काम कर सकते हैं।

इस बार के तमिलनाडु चुनाव में अभिनेता थलपति विजय उर्फ चंद्रशेखरन जोसेफ विजय का करिश्मा अब चूकता नज़र आ रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि वे भाजपा के कंधे से कंधा मिलाकर राय के सत्ताधारी करूणानिधि परिवार व उनकी डीएमके पार्टी के समक्ष एक महती चुनौती उपस्थित करेंगे या खुद को स्टालिन के विकल्प के तौर पर उभारने में सफल रहेंगे। पर ताजा जनमत रुझान बताते हैं कि उनकी पार्टी महज़ 8-10 फीसदी वोट शेयर पर ही सिमट सकती है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसका एक बड़ा कारण उनका क्रिश्चियन होना बताते हैं, क्योंकि राय में ईसाई आबादी महज़ 6 फीसदी के आसपास है। यह न तो संख्या बल में इतनी बड़ी या निर्णायक है। जबकि विजय की मां शोभा चंद्रशेखरन एक हिंदू है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08862)

टीबी मुक्त देवरिया की ओर बड़ा कदम- 192 ग्राम पंचायतों को मिला टीबी मुक्त का प्रमाणपत्र

देवरिया।

विश्व क्षय रोग दिवस पर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में हुआ भव्य आयोजन, ग्राम प्रधान हुए सम्मानित

विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर मंगलवार को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में एक भव्य जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में जनपद की 192 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया तथा संबंधित ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र एवं गांधी प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि क्षय रोग के उन्मूलन के लिए समय से जांच, पूर्ण उपचार और व्यापक जनजागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने में ग्राम प्रधानों और स्थानीय समुदाय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि मरीज से नहीं, मर्ज से दूरी बनाएं का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, सक्रिय रोगी खोज अभियान, नियमित जांच, उपचार एवं काउंसिलिंग के माध्यम से जनपद को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि जनपद की कुल 1121 ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग के समन्वय से व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत संभावित मरीजों की पहचान कर उनकी जांच, उपचार एवं अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र की सहभागिता एवं उच्च जोखिम समूहों की नियमित जांच से उपचार सफलता दर में सतत वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की यह पहल जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ रजनी पटेल, सीएमएस डॉ एचके मिश्रा, एसीएमओ डॉ अजय शाही, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ राजेश कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉ आरपी यादव, डिप्टी डीटीओ संजय गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। इस उपलब्धि से जहां टीबी उन्मूलन की दिशा में जिले को मजबूती मिली है, वहीं सम्मानित होने वाले ग्राम प्रधानों में भी अपार उत्साह देखा गया। अब अगले चरण में शेष ग्राम पंचायतों को भी टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे टीबी के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और इलाज पूरा करें, क्योंकि टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है।

आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर सौपा एसडीएम को ज्ञापन

कप्तानगंज(कुशीनगर)।

कप्तानगंज विकासखंड के ग्राम सभा देउरवा के ग्रामीणों ने मंगलवार को तहसील परिसर में पहुच विरोध प्रदर्शन कर नवीन परती व आबादी की जमीन पर हो रहे कथित अवैध निर्माण का विरोध किया। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी विनोद गुप्ता को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। जिस पर एसडीएम ने तत्काल जांच पर अवैध निर्माण को रोकने का निर्देश दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग उक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। जबकि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और यहां छठ पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थान पर छठ उपासना के साथ-साथ हिंदू समुदाय द्वारा पितरों का पिंडदान और बाल मुंडन संस्कार भी किए जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में पहले से ही याचिका विचाराधीन है। इसके बावजूद कुछ लोग विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। विरोध करने पर वे मारपीट और फौजदारी पर उतारू हो जाते हैं, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त जमीन को तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए और निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए, ताकि धार्मिक परंपराएं प्रभावित न हों। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान पिंटू वर्मा, शैलेंद्र उपाध्याय सुभाष उपाध्याय, सुरेंद्र सिंह, अनवर अली, पन्नीलाल, अनिल उपाध्याय, छेदी गोड, प्रभु गोड और मन्नू सिंह ,इश्रावती देवी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

शहीद दिवस पर निकली जागरूकता पदयात्रा, युवाओं ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

कुशीनगर।

मेरा युवा भारत कुशीनगर द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में शहीद दिवस के अवसर पर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम, रवींद्रनगर, पडरौना में जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील कुमार यादव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता, जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि कुमार निषाद, जिला युवा अधिकारी सचिन कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र तथा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी भारत लाल गोंड द्वारा भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके उपरांत युवाओं द्वारा शहीदों के पोस्टर के साथ जागरूकता पदयात्रा निकाली गई, जिसे उपस्थित अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना रहा। इस पदयात्रा की थीम ÷मेरा भारत, मेरी जिम्मेदारी÷ निर्धारित की गई थी। पदयात्रा के दौरान युवाओं ने देशभक्ति से ओत-प्रोत नारों के साथ उत्साहपूर्वक भागीदारी की तथा शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का संचालन नवनीत सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर वीरेंद्र प्रताप सिंह, सूरज गौतम (हॉकी कोच), सुशील मिश्रा, पंकज यादव, सोनू शर्मा, विनय चौहान, विशाल सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का विशेष योगदान रहा।

मशाल लेकर सड़कों पर उतरे शिक्षक, टेट से छूट की मांग तेज

पडरौना, कुशीनगर। शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व सेवारत शिक्षकों को टीईटी से मुक्त कराने की मांग को लेकर शिक्षक संगठन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) ने मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन तेज कर दिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के आह्वान पर जिले में भी शिक्षकों ने सड़क से न्यायपालिका तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। इसी क्रम में कुशीनगर में सुभाष चौक पडरौना से अंबेडकर चौक कटकुईया तक सैकड़ों शिक्षकों ने हाथों में मशाल लेकर विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान ÷टीईटी वापस लो÷ और ÷काला कानून वापस लो÷ जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शिक्षकों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। मशाल जुलूस में यूटा गोरखपुर मंडल अध्यक्ष विनय प्रकाश सिंह सिसोदिया ने हौसला बढ़ाया, जबकि जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा और जिलामंत्री सुबोध शुक्ला के संयुक्त नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जुलूस में बीर बहादुर, अनंत सिंह, रामेश्वर गुप्ता, आनंद कुमार, विष्णु कुशवाहा, शारदा कुशवाहा, राकेश प्रसाद, रमेश वर्मा, राघवेंद्र वर्मा, नियाज अहमद, दयानाथ गुप्ता, मिथिलेश, पंकज यादव, सुनील पाल, अमरदीप शुक्ला, अखिलेश मिश्रा, अनवर सहित सैकड़ों शिक्षक शामिल रहे। संगठन ने जुलूस में शामिल होकर आवाज बुलंद करने वाले सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

जिला सैनिक बन्धु की बैठक सम्पन्न, पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश

कुशीनगर।

मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला सैनिक बन्धु की बैठक विकास भवन सभागार में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में मुख्य विकास अधिकारी ने उपस्थित पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों का अभिनन्दन करते हुए पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की। इसके पश्चात बैठक की औपचारिक कार्यवाही प्रारम्भ हुई, जिसमें कुल 28 पूर्व सैनिक एवं वीरांगनाएं/विधवाएं उपस्थित रहीं। बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों से संबंधित कुल 6 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें जमीनी विवाद, न्यायालय में लंबित प्रकरण, शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, निजी भूमि से गांव का पानी निकाले जाने से फसल क्षति तथा भूमि पैमाइश से जुड़ी समस्याएं शामिल रहीं। इसके अतिरिक्त एक प्रार्थना पत्र सेवारत सैनिक की ओर से प्राप्त हुआ, जो शहीद परिवार के कल्याण से संबंधित था। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का समाधान पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाए तथा प्रकरणों की प्रगति से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को नियमित रूप से अवगत कराया जाए। साथ ही लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई कर अनावश्यक विलंब न होने देने के निर्देश भी दिए। बैठक में अभय कुमार सुमन (जिला उद्योग केंद्र), सहायक कोषाधिकारी सहित पूर्व सैनिक कैप्टन लाल बहादुर त्रिपाठी, कैप्टन शमसुद्दीन अंसारी, कैप्टन दयाशंकर पाण्डेय, हवलदार शारदा प्रसाद एवं अन्य पूर्व सैनिक एवं वीरांगनाएं/विधवाएं उपस्थित रहीं। बैठक का संचालन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के प्रभाकर नाथ तिवारी (कनिष्ठ सहायक), राजेश कुमार गुप्त, श्रीमती धर्मशीला देवी, जालंधर प्रसाद एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

तीन नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी, विरोध पर मारपीट; कार्रवाई न होने से परिजनों में आक्रोश

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसी रामकोला थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने 18 मार्च की शाम उस समय घटना को अंजाम दिया, जब तीनों लड़कियां खेत से तोरिया फसल की मड़ाई कर घर लौट रही थीं। पीड़िताओं के अनुसार, रास्ते में आरोपी युवक ने उनके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर उसने उनके साथ मारपीट की और जानमाल की धमकी भी दी। किसी तरह तीनों लड़कियां घर पहुंचीं और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों का आरोप है कि जब वे शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की और उनकी बाइक छीन ली। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि घटना के चार दिन बीत जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया बम की धमकी वाला मेल, मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं का भी नाम

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को बम धमकी वाला ईमेल मिला है। ईमेल में विधानसभा भवन और विधानसभा दिल्ली मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के मुताबिक, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को भी धमकी मिली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को भी धमकी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को भी धमकी मिली है। मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियां अलर्ट हो गईं। पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बता दें इससे पहले भी समय-समय पर इसी तरह ई-मेल के जरिए अलग-अलग स्कूलों, नामी प्रतिष्ठानों और विशिष्ट लोगों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रही है। लेकिन जांच पड़ताल में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। विधानसभा में बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल के बाद डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। विधानसभा की सुरक्षा और उत्तरी जिले की बम निरोधक दस्ते की टीमों द्वारा भी छानबीन की गई है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सुबह 7:49 बजे पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को ईमेल पर ईमेल आया और 7:28 बजे विधानसभा की ईमेल पर धमकी भरा मेल आया था। धमकी भरा ईमेल मिलने पर भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा, हम डरेंगे नहीं, यह भाजपा सरकार है, जो विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है और दिल्ली में विकास कार्य जारी है... मुझे विश्वास है कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा और इस बार बजट और भी बड़ा होगा। वहीं भाजपा विधायक अनिल गोयल ने कहा, यह एक अफवाह थी। सब कुछ सुरक्षित है, हम बैठक के लिए जा रहे हैं। जुलाई, 2025 में 40 से 50 स्कूलों को बम धमकी वाले ई-मेल मिले थे। ये सभी संदेश झूठे निकले थे। वहीं, पिछले साल सितंबर में एक ही दिन में 300 से अधिक स्कूलों और कई हवाई अड्डों को धमकी भरे ई-मेल मिली थी। इन धमकियों को एक समूह टैरर राइज 111 द्वारा भेजा गया था। इसी महीने शालीमार बाग, द्वारका और साकेत स्थित मैक्स अस्पतालों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन, वहां भी कुछ नहीं मिला। साल 2026 में भी यह सिलसिला जारी रहा। फरवरी और मार्च में करीब 15 से ज्यादा स्कूलों के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहर लाल किला और दिल्ली विधानसभा को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस जांच में पाया गया कि अधिकतर ई-मेल वीपीएन और एन्क्रिप्टेड सर्वरों के माध्यम से भेजे गए, जिससे प्रेषक की वास्तविक पहचान छुपी रही। साइबर सेल और तकनीकी विशेषज्ञों को जांच में शामिल किया गया। कुछ मामलों में यह भी सामने आया कि धमकी भेजने वाले नाबालिग थे। जुलाई 2025 में एक 12 वर्षीय छात्र द्वारा मजाक में भेजी गई धमकी का मामला उजागर हुआ। उसने स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य स्कूल बंद करवाना था।

अपराधी का दुस्साहस मतलब यमराज का टिकट, यूपी में अराजकता बर्दाश्त नहीं - मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 'निवेश मित्र 3.0' सिंगल विंडो सिस्टम के शुभारंभ अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश का प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए पिछले 9 वर्षों में व्यापक प्रयास किए गए हैं। सीएम ने 2017 की स्थिति को याद करते हुए कहा कि जब निवेश के लिए उद्यमियों को यूपी आने का आमंत्रण दिया जाता था, तो वे इस पर हंसते थे और कई लोग तो पहले से ही यहां न आने का संकल्प लेने की बात करते थे। उस समय प्रदेश की छवि इतनी खराब थी कि निवेश की बात करना भी असहज लगता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नकारात्मक धारणा के पीछे दो प्रमुख कारण थे।

पहला, पहचान का संकट और दूसरा, माफिया व आपराधिक गिरोहों का प्रभाव, जो हर जिले और थाने में समानांतर सत्ता चलाकर उद्यमियों, व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। तब हमने इस माफिया की कमर तोड़ने, इसे पूरी तरह कुचलने का निर्णय किया।

अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति

हमने तय किया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस की वह नीति पहले दिन से आज तक अनवरत बनी हुई है। सीएम ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मानकर चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है।

उद्योगों के संचालन में बाधा या अराजकता बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में उद्योगों के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं ट्रेड यूनियन या अन्य किसी नाम पर उद्योगों को बाधित करने की कोशिश की जाती है, तो वह स्वयं तत्काल संज्ञान लेते हैं और जरूरत पड़ने पर रात में ही संबंधित डीएम और एसपी को निर्देश देकर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराते हैं, ताकि निवेश और उद्योगों का माहौल प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर की 'लाल इमली' मिल जैसे उदाहरण बताते हैं कि कैसे पहले ट्रेड यूनियनों के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के कारण एक समय का प्रमुख टेक्सटाइल हब बंद होकर खंडहर में बदल गया और हजारों परिवार प्रभावित हुए। पिछली सरकारों ने उद्योगों की संभावनाओं को नकारा, लेकिन वर्तमान सरकार ने अनुकूल माहौल देकर निवेश को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जनता का विश्वास लगातार मिल रहा है।

ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे

मोदी बोले- आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह काम करना होगा

*पश्चिम एशिया के हालात भारत के लिए चिंताजनक हैं।
*व्यापार मार्ग और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई।
*भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, शांति हेतु कूटनीति पर जोर।

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए हैं। ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस-तेल, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है।

राज्य सरकारों से अपील- ऐसे संकट के समय में गरीबों पर, श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ मिलता रहे। राज्य सरकार इसके लिए विशेष व्यवस्था करे। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव होते हैं। जहां से शिकायतें आती हैं, वहां कार्रवाई कीजिए। संकट कितना भी बड़ा है, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। हमें हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म तेजी से करते रहने होंगे।

किसानों को मैसेज- सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए जरूरी तैयारियां की है। किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें सफलता के लिए राज्यों का सहयोग जरूरी है। राज्यों की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

तेल, गैस और महंगाई पर - कोरोना के समय में जैसे अलग-अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों के एम्पॉवर्ड ग्रुप बने थे, वैसे ही कल 7 एम्पॉवर्ड ग्रुप बनाए गए हैं। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल-डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई जैसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करेंगी।

होर्मुज स्ट्रेट संकट पर- हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल-डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू फंसे हैं। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज जैसे जल मार्ग में रुकावट अस्वीकार है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी जहाजों के सतत् आवागमन के लिए प्रयास कर रहा है।

गल्फ देशों में फंसे भारतीयों को संदेश- देश-विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जंग शुरू होने से अब तक 3 लाख 75 हजार से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। ईरान से एक हजार से ज्यादा भारतीय लौटे हैं। इनमें 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मौत हुई है। यह दुखद है। उनके परिवार को मदद दी जा रही है। जो घायल हैं उन्हें इलाज दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री हताश दिख रहे थे- संजय राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने 24 मार्च को पश्चिम एशिया संघर्ष के संबंध में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नियंत्रण खो चुके और निराश प्रतीत हो रहे थे। एएनआई से बात करते हुए राउत ने कहा कि मोदी युद्ध शुरू होने के 25 दिन बाद सदन में आए और उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव-भाव और भाषण को देखकर साफ पता चलता है कि वे अवसादग्रस्त हैं। राउत ने आगे कहा कि मोदी जी ने अपना आपा खो दिया है और ऐसा लगता है कि वे ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहना चाहते। मोदी खुद ही सत्ता छोड़ देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी के 25 मिनट के भाषण पर की गई टिप्पणी के संदर्भ में राउत ने कहा कि इस गंभीर संकट के समय भाषण में अपेक्षित स्पष्टता नहीं दी गई।

ईरान युद्ध पर भारत में भी बढ़ी हलचल, सरकार ने चर्चा के लिए बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, महिला आरक्षण पर भी चर्चा

नई दिल्ली । सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और देश पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे पहले दिन में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थिति का आकलन करने और भारत की रक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और डीआरडीओ अध्यक्ष समीर कामत सहित वरिष्ठ सैन्य और रक्षा अधिकारी शामिल हुए। पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापार मार्गों में भारी व्यवधान की खबरें आ रही हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद स्थिति और बिगड़ गई।

इसके जवाब में, ईरान ने कई खाड़ी देशों में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। इन जवाबी कार्रवाइयों ने क्षेत्र को और अधिक अस्थिर कर दिया है, समुद्री आवागमन को प्रभावित किया है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों और आर्थिक स्थितियों में अनिश्चितता पैदा कर दी है।

राजद प्रमुख लालू यादव को हाईकोर्ट से लगा झटका, सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली । नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सीबीआई की एफआईआर और आरोपपत्र को रद्द करने की लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। यह नौकरी के बदले जमीन घोटाला पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर (मध्य प्रदेश) स्थित जोन में ग्रुप डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्तियां लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल (2004-2009) के दौरान हुई थीं।

इन नियुक्तियों के बदले में, कथित तौर पर जमीन के पार्सल लालू प्रसाद के परिवार या सहयोगियों के नाम पर उपहार के तौर पर या हस्तांतरित किए गए थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने सोमवार को नौकरी के बदले जमीन

मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मनोज जैन की एकल पीठ ने राबड़ी देवी की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की है। राबड़ी देवी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 1,600 से अधिक अप्रयुक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार किया गया था। यह दस्तावेज जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा जब्त किए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इन्हें अपनी चार्जशीट में शामिल नहीं किया है। 18 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी और उनके पति पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल की इस प्रारंभिक अवस्था में सभी अप्रयुक्त दस्तावेज एक साथ उपलब्ध कराना घोड़े से पहले गाड़ी रखने जैसा होगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपियों को हर दस्तावेज स्वतः प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अभियोजन पक्ष पहले अपने सबूत पेश करेगा, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर ही आगे की कार्रवाई होगी।

सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती; साथ में राहुल और प्रियंका

नई दिल्ली ।कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार को अचानक बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिया गांधी को फेफड़े से संबंधित समस्या के कारण अस्पताल में दाखिल किया गया है। उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी अस्पताल में मौजूद हैं। परिवार के सदस्य उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

डॉक्टरों की विशेष टीम कर रही देखरेख

अस्पताल प्रशासन ने उनकी वर्तमान स्थिति को स्थिर बताया है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी देखरेख कर रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उनकी सेहत को लेकर चिंता का माहौल है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

दिल्ली का हरित बजट पेश, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- कूड़े के पहाड़ होंगे खत्म,लगेंगे 35 लाख पौधे; खर्च होंगे 22,236 करोड़

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 2026-27 के बजट को हरित बजट बताते हुए सतत विकास और स्वच्छ पर्यावरण के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस पहल के लिए पूरे बजट का 21 प्रतिशत आवंटित किया गया है। बजट के अनुसार, कुल परिव्यय का 21.44 प्रतिशत यानी 22,236 करोड़ रुपये हरित विकास पहल के लिए आवंटित किए गए हैं। पर्यावरण और वन क्षेत्रों के लिए 822 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के 505 करोड़ रुपये से 62.7 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार शहरी वनों, पार्कों और हरित क्षेत्रों के विकास के माध्यम से राजधानी का हरित दिल्ली का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसायटी के लिए अलग से 25 करोड़ रुपये आवंटित कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि अगले चार साल में दिल्ली में पीपल, आम और नीम जैसे 35 लाख स्वदेशी पौधे लगाए जाएंगे और नए वन क्षेत्रों का भी विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विकास के लिए 130 करोड़ रुपये और वन्यजीव संरक्षण के

लिए 44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपायों के लिए 300 करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रही है, जिसमें यांत्रिक स्वीपर, एंटी-स्मॉग गन और वॉटर स्प्रिंकलर शामिल होंगे। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष रूप से 204 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। वित्त विभाग का प्रभार भी संभाल रहीं गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार विश्व बैंक के सहयोग से उन्नत तकनीकी समाधान और निगरानी प्रणालियों को लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। निगरानी प्रणालियों (एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र-आईसीसीसी), युद्धकक्ष संचालन, मोबाइल ऐप और वास्तविक समय में ट्रैकिंग के लिए अतिरिक्त दो करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हरित बजट पेश करते हुए गुप्ता ने कहा कि सरकार अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता को वर्तमान 7,000 टन से बढ़ाकर 15,000 टन प्रतिदिन करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नरेला, ओखला, गाजीपुर और तेहखंड में स्थित अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार के लिए प्रावधान किए गए हैं। गुप्ता ने कहा, हमने पुराने कूड़े के पहाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, गाजीपुर में 16 प्रतिशत, भलस्वा में 54 प्रतिशत और ओखला में 68 प्रतिशत की कमी आई है। यह शहर में कचरा प्रबंधन के तरीके में एक स्पष्ट और ठोस बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 1,500 टन गोबर अपशिष्ट को भी संसाधित करके ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ हम ई-कचरा प्रबंधन के लिए सुनियोजित योजना भी शुरू कर रहे हैं।

पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी ने ट्रंप से की बात, होर्मुज पर जताई चिंता

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तर पर अहम बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात कर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने की जरूरत पर दोनों नेताओं ने गंभीरता से विचार किया, क्योंकि यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। अमेरिकी राजदूत की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा पर फोकस रहा। दोनों नेताओं ने माना कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला रहना जरूरी है ताकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब इसराइल-ईरान तनाव के कारण क्षेत्र में

अस्थिरता बढ़ रही है।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

बातचीत के दौरान भारत ने तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुगम बने रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में स्थिरता और शांति के प्रयासों को लेकर संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई।

श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी मोदी ने की चर्चा

पीएम मोदी ने मंगलवार को ही श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अवरोधों पर विचार किया। इस बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, राष्ट्रपति दिसानायके से पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और इस दौरान हमने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले व्यवधानों पर विशेष ध्यान दिया गया। करीबी और भरोसेमंद साझेदार होने के नाते, हमने साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस दौरान हमने भारत-श्रीलंका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा की।

ट्रंप ने बातचीत का किया था दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के एक दिन पहले दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है और कई मुद्दों पर सहमति बनने की स्थिति है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समझौता चाहते हैं और अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ी तो कुछ ही दिनों में समाधान निकल सकता है। ट्रंप का यह भी कहना है कि बातचीत की पहल ईरान की तरफ से हुई है और अमेरिका सिर्फ उसका जवाब दे रहा है।

ईरान ने किया था सभी दावों से इनकार

हालांकि ईरान ने ट्रंप के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। ईरान के शीर्ष नेताओं ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फर्जी खबरें फैलाकर तेल बाजार और वैश्विक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ईरान का कहना है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोले - हमारी विदेश नीति मजाक बन गई

ट्रंप को पता होता है मोदी क्या करेंगे क्या नहीं, राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया संकट पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई है और एक व्यक्तिगत नीति बनकर रह गई है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए गांधी ने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री की छवि खराब है, तो हमारी विदेश नीति भी खराब है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारत का कूटनीतिक रुख मोदी की निजी विदेश नीति में बदल गया है और कहा कि हर कोई इसे एक मजाक समझता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर बढ़ते वैश्विक संकट के बीच भारत की विदेश नीति से समझौता करने का आरोप लगाया। गांधी ने आरोप लगाया कि भारत की कूटनीतिक स्थिति अब स्वतंत्र नहीं रही और सरकार अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के प्रभाव में काम कर रही है। गांधी ने अपनी आलोचना को वैश्विक धारणाओं से जोड़ते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भली-भांति पता है कि मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उन्होंने अपने इस आरोप को दोहराया कि सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं है, और जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री वही करेंगे जो अमेरिका और इजराइल कहेंगे। वे भारत और उसके किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। विपक्ष के नेता ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के संदर्भ में संसद को संबोधित करते हुए मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी का जिक्र करने पर भी आपत्ति जताई। गांधी ने कहा कि कल उन्होंने एक अप्रासंगिक भाषण दिया। वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही व्यवहार करना चाहिए, उनका कोई पद नहीं है। महामारी के दौरान झेली गई कठिनाइयों का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा, -मोदी जी ने कहा कि कोविड जैसा समय आने वाला है। वे भूल गए हैं कि तब क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे और किस तरह की त्रासदी घटी थी। उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा हालात में महामारी का जिक्र करना असंवेदनशीलता और समझ की कमी दर्शाता है।